साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 09-15 अक्टूबर 2023 वर्ष-9, अंक-26

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ:-8,मूल्यः- 2 रुपए

-सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा-मामा को आशीर्वाद दीजिए

एक करोड़ किसानों को 'सम्मान' के साथ फसल बीमा के मिले पैसे

-1561 करोड़ किसान सम्मान निधि,बीमा के 1058 करोड़ जारी

-प्रदेश का जैसा विकास हमने किया, वैसा किसी ने नहीं किया

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे। जहां उन्होंने व्यंकटेश लोक का लोकार्पण किया। इसके बाद सभा स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं पर पुष्प वर्षा करने के बाद कन्या पूजन किया। उन्होंने फसल बीमा के 30 लाख किसानों को 1058 करोड़ और 72 लाख किसानों को सीएम किसान निधि के 1561 करोड़ रुपयों का अंतरण सिंगल क्लिक से किया। इसके साथ ही 4 लाख 30 हजार पट्टों का वितरण किया। किसान सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम जबलपुर आ रहे हैं, मुझे जाना है। यहीं से मैहर जिला भी मां शारदा को समर्पित कर रहा हूं। जैसा विकास भाजपा ने मप्र का किया है। वैसा कभी कांग्रेस ने नहीं किया। मैं दिन भर लोकार्पण शिलान्यास कर रहा हूं, विकास की गंगा बह रही है। कमलनाथ सीएम थे, हर वक्त रोते रहते थे, कहते थे पैसा नहीं है, ऐसे आदमी को सीएम बनाना चाहिए क्या। विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।

सीएम शिवराज ने कहा कि हम दौरी सागर बांध, नहरें, सड़कें स्कूल सब बना रहे हैं। 157 करोड़ 84 लाख का लोकार्पण और 959 करोड़ के शिलान्यास आज हो रहे हैं। अभी मां शारदा लोक भी बनेगा। याद करो जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिंचाई की क्या व्यवस्था थी।

2.84 लाख करोड़

तब साढ़े 7 लाख हेक्टेयर की व्यवस्था थी आज 47 लाख हेक्टेयर का इंतजाम है। आने वाले समय मे 1 लाख हेक्टेयर की व्यवस्था करेंगे। नहर ही नहीं पाइप लाइन से पानी की सप्लाई देंगे। पहले 100 एमटी अनाज होता था आज 700 लाख पैदा होता है। पहले 18 परसेंट पर कर्ज मिलता था आज जीरो परसेंट में मिल रहा है। इन तीन सालों में 2 लाख 84 हजार करोड़ किसानों के खाते में डाले हैं।

हमे 7 बार कृषि कर्मण अवॉर्ड

सीएम ने कहा कि अकेले फसल बीमा योजना में 20 हजार करोड़ किसानों को दिए। हर फसल का उत्पादन बढ़ा है। हमे 7 बार कृषि कर्मण अवॉर्ड मिला है। सीएम ने किसान निधि शुरू की तो हमने भी उसमे योगदान दिया। अब 6 हजार पीएम के और 6 हजार सीएम के आएंगे। क्या कभी कांग्रेस ने दिया था। लाड़ली बहना में भी दे रहे हैं। ये भाजपा की सरकार है, कोई कसर नहीं छोड़ती। हमने सब कुछ देने की कोशिश की। अब हम अनुदान पर ट्रांसफॉर्मर लगाने की योजना फिर शुरू कर रहे है। किसानों को खाद की भी कोई कमी नहीं रहेगी।

राहत राशि भी देंगे

सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफ करने को कहा लेकिन किया नहीं, हमने 2200 करोड़ का ब्याज भी चुकाया। बारिश के गैप के कारण अगर किसानों की फसल का नुकसान हुआ होगा तो उसकी भरपाई होगी। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए हैं। राहत राशि भी देंगे और फसल बीमा का पैसा भी दिलाएंगे। आज 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना और 2 लाख किसानों को सम्मान निधि की रकम डाली जाएगी। किसान भाइयों से भाजपा, मोदी के साथ चलने का आह्वान करते हुए कहा कि उनका साथ दीजिए।

पीएम और मामा को आशीर्वाद दीजिए | सीएम शिवराज ने कहा कि माताएं बहने हैंडपम्प से पानी भरने जाती थी। इसलिए नल जल योजना शुरू की। कौन सा ऐसा पक्ष है जिसमे भाजपा सरकार ने काम न किया हो। मेधावियों को लैपटाप - स्कूटी दिलाई। किसानों से कहा कि मैं वचन देता हूं कि आप किसानों ने फसल का उत्पादन 7 सौ फीसदी बढ़ाया है। हमने खेती से आमदनी दो गुनी की है। जो काम करें, उसका साथ देना चाहिए। आप सब पीएम मोदी,भाजपा और मामा को आशीर्वाद दीजिए।

केंद्र ने बोर्ड के गठन के लिए जारी की अधिसूचना

हल्दी बोर्ड बनाने मिली मंजूरी अब किसानों को होगा फायदा

भोपाल। जागत गांव हमार

हल्दी की खेती करने वाले किसानों की वर्षों पुरानी मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया है। किसानों की बोर्ड बनाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग उठाते रहे हैं। देश में फिलहाल हल्दी की खेती को बढ़ावा देने और एक्सपोर्ट से जुड़े काम मसला बोर्ड के तहत होते है। इसलिए इसका अलग बोर्ड बनाने की मांग होती रही है। देश में फिलहाल हल्दी का 11.53 लाख टन उत्पादन होता है। दुनिया में हल्दी उत्पादन का 78 फीसदी है। तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती होती है। प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन (6,973 किलो) तेलंगाना में ही होता है। मसाला बोर्ड के मुताबिक 2018-19 में 1,33,600 टन हल्दी का एक्सपोर्ट किया गया। इससे 1416.16 करोड़ मिले। इम्युनिटी बूस्टर होने की वजह से कोरोना काल में हल्दी एक्सपोर्ट बढ़ा था।

अभी सरकार ऐसे करती है मदद-

केंद्र सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत निजामाबाद क्षेत्र में एक्सपोर्ट प्रमोशन गतिविधियों और उत्पादन पर राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाने के लिए एक रीजनल ऑफिस एवं मसाला बोर्ड विस्तार केन्द्र स्थापित किया है। हल्दी सहित मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड का तेलंगाना के वारंगल, हैदराबाद, निजामाबाद और खम्मम में कार्यालय हैं। किसानों को होगा सीधा फायदा टर्मरिक बोर्ड बनेगा तभी किसान को इसका एमएसपी मिल पाएगा। एमएसपी मिलेगा तो किसानों को फायदा होगा।

समर्थन पर धान बेचने अब 15 अक्टूबर तक होगा पंजीयन

भोपाल। मप्र में एमएसपी पर धान, ज्वार एवं बाजरा बेचने के लिए किसान अब 15 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। सरकार ने एमएसपी पर धान, ज्वार एवं बाजरा बेचने के लिए पंजीयन कराने की अंतिम तिथि पांच अक्टूबर को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया है। प्रदेश में ई-उपार्जन के अंतर्गत किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने के लिए पहले पंजीयन कराना होता है। पटवारियों की हड़ताल के कारण खसरे में फसल की बोवनी की जानकारी दर्ज नहीं हो पाई थी। इसके कारण पंजीयन नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसके आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि किस किसान ने कितने क्षेत्र में कौन सी फसल बोई है।

-गांवों में जर्जर सड़कों के लिए फंड तक नहीं

सरपंचों को जनता के आक्रोश का करना पड़ रहा सामना

एक साल बाद भी मध्यप्रदेश की पंचायत बदहाल

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश की 23 हजार से ज्यादा पंचायतों में पिछले साल जुलाई में चुनाव हुए थे। सरपंचों को चुने हुए एक साल से ज्यादा समय हो गया है। बीते एक साल में पंचायतों के सरपंच सड़क, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी निर्माण जैसे काम करवाने के लिए जनपद, जिला पंचायत और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं। स्थिति यह है कि पंचायतों को फंड ही नहीं मिल पा रहा है। इससे पंचायत सरपंच परेशान हो चुके हैं। पंचायत सरपंचों का कहना है कि वे आवासहीनों को आवास नहीं दिला पा रहे हैं। गरीब हितग्राहियों के राशन कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के सरपंच बीते एक साल से सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार का जरिया बनकर रह गए हैं। उनके गांवों के सारे विकास कार्य ठप हो गए हैं। अगर सरकार पंचायतों को राशि उपलब्ध नहीं कराती है, तो वे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जनता के सामने अपने जनप्रतिनिधियों के लिए वोट मांगने तक नहीं जा पाएंगे।

नल-जल योजना ने खराब कर दीं सड़कें - प्रदेश के सभी जिलों में नल-जल योजना का काम चल रहा है। नल-जल योजना के नाम पर सड़कों को खोद दिया है। इसके बाद भी ज्यादातर नल-जल योजना फेल है। नल-जल योजना के जरिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इधर, नल-जल योजना के नाम पर गांवों की सड़कों को ठेकेदारों ने खोद दिया। इसके बाद इनका निर्माण तक नहीं हो पा रहा है। इन सड़कों के निर्माण के लिए भी पंचायतों को राशि नहीं मिल रही है।

राशि नहीं कर पा रहे खर्च

वर्तमान में नल जल योजना के कारण गांव की सड़क भी जगह- जगह से उखड़ गई हैं। कई सड़क वर्षों पुराने निर्माण होने से अति दयनीय स्थिति में है। 15वें वित्त की टाइट/एनटाइड की बंदिशों के कारण हम सीसी सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त राशि खर्च कर नहीं पाते हैं। अभी भी समय है हमें अगर इन मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाए तो हम ग्रामीण विकास में अपने कार्यकाल को सफलतम बना सकते हैं। हमसे पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा सहयोग लिया जा रहा है। चुनाव में भी वह हमसे अपेक्षा रख रहे हैं अतः हमें भी अपनी मांगों को उनके समक्ष रखना होगा।

प्रदेश के सरपंचों की मांगें

- प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल/मुख्यमंत्री जन आवास का पोर्टल शीघ्र अति शीघ्र खोला जाए।
- हम लोगों के कार्यकाल का 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है अभी तक हम किसी भी गरीब का एक भी मकान नहीं बनवा पाए हैं।
- गांव में हमसे बार-बार आवास के लिए मांग की जाती है और हम बार-बार पोर्टल खुलने का आश्वासन देते हैं।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके अंतर्गत गरीब परिवार को निशुल्क गैस कनेक्शन मिलता है वह पोर्टल भी अभी तक बंद है हमारे सामने दो-दो चुनाव हैं।
- पंचायतों को विकास कार्य के लिए 15वें वित्त और राज्य मद से पांचवा वित्त आयोग राशि की किस्त भी शीघ्र जारी की जाए।
- जिस प्रकार नगरीय निकायों को कायाकल्प के तहत सीसी सड़कों के लिए विशेष पैकेज दिया गया है हमारी ग्राम पंचायतों को भी सीसी सड़क निर्माण के लिए पैकेज की किस्त जारी की जाए।

ग्रेजुएट किसान नौकरी की आस छोड़ करने लगा फार्मिंग

टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती,20 लाख तक कमाई

अशोकनगर। जागत गांव हमार

अशोकनगर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बगुल्या गांव के रहने वाले युवा किसान सोनू राय ने छह साल पहले परंपरागत खेती छोड़ सब्जी की खेती शुरू की। टमाटर, मिर्ची और बैंगन की खेती ने सोनू की किस्मत बदल दी। ग्रेजुएशन के बाद गांव आकर सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ ही खेती में पिता का हाथ बंटाने लगा। परंपरागत खेती में साल-दर-साल लागत बढ़ती जा रही थी। मुनाफा कम होता जा रहा था। इसी बीच कुछ दोस्तों ने बताया कि सब्जी की खेती में अच्छा मुनाफा है। दोस्तों की सलाह पर सोनू ने सब्जी की खेती शुरू की। कुछ ही महीनों में अच्छे संकेत मिलने लगे तो रकबा भी बढ़ा दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और अब 12 बीघा खेत में सब्जी की पैदावार हो रही है। टमाटर, मिर्ची और बैंगन से 7 से 8 महीने तक पैदावार मिल रही है। 12 बीघा से एक सीजन में 20 लाख रुपए तक आमदनी हो रही है, जबकि इसमें 3.50 लाख रुपए की ही लागत आती है। हालांकि, पहले साल जब सब्जी की खेती शुरू की तो ड्रिप लगाने का खर्च ज्यादा आया था। अशोकनगर की कृषि उपज मंडी शरबती गेहूं के लिए जानी जाती है। जिले में सबसे ज्यादा शरबती गेहूं की पैदावार होती है। सब्जी की खेती करने वाले सोनू राय ने इस पहचान को बदला है। अब बगुल्या गांव को सब्जी वाला गांव कहा जाने लगा है। वहीं अशोकनगर की मंडी में सब्जियों के खरीदार भी जुटने लगे हैं।

ऐसे तैयार करते हैं खेत

गर्मी के सीजन में किसी भी प्रकार की फसल नहीं लगाई जाती है। इस दौरान गहरी जुताई करके खेत को छोड़ दिया जाता है। जैसे ही जुलाई के महीने में बारिश शुरू होती है, खेत को तैयार करने लगते हैं। फिर से जुताई करने के बाद ड्रिप डाल देते हैं। इसके बाद मल्चिंग डालकर पौधे लगाने के लिए मल्चिंग में छेद कर देते हैं।

25 दिन में पौधे तैयार

सब्जी उत्पादन के लिए 15 जुलाई के आसपास पौध लगाई जाती है। घर पर ही मैंटी लगाकर पौध तैयार करते हैं। 25 दिन तक उसकी पूरी तरह से देख-रेख करने के बाद उसे खेतों में लगना शुरू करते हैं। 5 से 6 दिन में सभी पौधे लगा दिए जाते हैं।

40 रुपए किलो मिर्च

किसान सोनू राय ने बताया कि इस समय सब्जी के अच्छे दाम मिल रहे हैं। टमाटर 18 रुपए किलो, मिर्च 40 रुपए किलो और बैंगन 12 से 15 रुपए किलो बिक रहा है। इस सीजन में इसी तरह से दाम मिलते रहे तो टमाटर 12 लाख रुपए का बिक जाएगा, जबकि मिर्च और बैंगन तीन- तीन लाख रुपए में बिक जाएंगे।

70 दिन में टमाटर तैयार

पौधे लगाने के बाद एक से डेढ़ महीने तक पौधों की सबसे ज्यादा देखभाल करने की जरूरत होती है। 45 दिन के बाद मिर्च का उत्पादन शुरू हो जाता है। जबकि बैंगन का उत्पादन 45 से 50 दिन में होने लगता है। हालांकि टमाटर में कुछ समय ज्यादा लगता है।

किसान सोनू राय की जुबानी उनकी सफलता की कहानी

मैंने साल 2012 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद मेरा ध्यान केवल सरकारी नौकरी पर था। नौकरी के लिए तैयारी के दौरान ही मैं पिता के साथ परंपरागत खेती में हाथ बंटाने लगा। कुछ दिनों में ही मैं समझ चुका था कि सरकारी नौकरी लगना संभव नहीं है। मेरे पास 15 बीघा जमीन है। पिताजी परंपरागत खेती के साथ घर का खर्च चलाने के लिए सब्जी की खेती करते थे। मैं समझ चुका था कि इस खेती से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। उस समय मेरे पिता एक से दो बीघा में सब्जी लगाते थे, बाकी में गेहूं की खेती करते थे। सब्जी बहुत कम मात्रा में होती थी, जिसका उपयोग अपने घर के लिए करते थे। जो सब्जी बच जाती थी, उसे गांव के ही बाजार में बेच देते थे। कुछ साल तक पिताजी के साथ खेतों में काम किया। इसी बीच कुछ दोस्तों ने सब्जी की खेती के फायदे बताए। इसके बाद मैंने ड्रिप और मल्चिंग के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग से संपर्क किया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ड्रिप के लिए अनुदान दिया जाता है। जैसे ही विभाग से सहायता का आश्वासन मिला तो मैंने सब्जी की खेती करने की ठान ली। 2017 में मैंने पहली बार सब्जी की खेती वैज्ञानिक तरीके से शुरू की। पहले साल दो बीघा खेत में ड्रिप लगाकर खेती करना शुरू किया। मात्र दो बीघा खेत से होने वाली पैदावार से ही अच्छा मुनाफा मिलने लगा। इसके बाद लगातार खेती का रकबा बढ़ाता गया। धीरे-धीरे पूरे खेत में ड्रिप लगवा दी। कुछ साल में ही मैंने अपनी 10 से 12 बीघा जमीन में टमाटर, मिर्च और बैंगन लगाए। इस दौरान कई ऐसे दौर भी आए, जब अच्छी खासी कमाई हुई। 2021 में सवा दो बीघा के टमाटर से 8 लाख कमाई हुई। इस प्रकार की लगातार आय बढ़ने की वजह से हौसला बढ़ता चला गया। इस साल 12 बीघा में टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन की खेती की है। इसमें 6 बीघा में टमाटर, 3.5 बीघा में बैंगन और 2.5 बीघा में हरी मिर्च लगाई है। काम करने के लिए मजदूर लगाए हैं। खुद ही अशोकनगर की मंडी में बेचने के लिए जाते हैं। हर दिन गांव से टैक्सी में पूरी सब्जी भर के मंडी ले जाते हैं। पिछले साल 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी टमाटर से, 2.5 से 3 लाख रुपए की लाल मिर्च और इतनी ही कमाई हरी मिर्च से हुई थी। इस बार 20 लाख रुपए आमदनी की उम्मीद है।

गांव के 6 लोगों को रोजगार

इसमें परिवार सहित 6 लोग काम करते हैं। शुरुआत से लेकर उत्पादन की तुड़ाई तक का काम आसानी से कर देते हैं। पौधारोपण के समय लगभग 5 से 6 दिन सबसे ज्यादा काम होता है। इसके बाद बीच में निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। फिर जैसी कोई उत्पादन शुरू हो जाता है तो तुड़ाई का काम करते हैं।

एक पौधे में 10 किलो पैदावार

एक मिर्च या टमाटर के पौधे से 8 से 10 किलो तक का उत्पादन लिया जा सकता है। टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। इसके अलावा बाकी महीने एक जैसा उत्पादन रहता है। एक बीघा के लिए 350 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 6 बीघा टमाटर के लिए 2 किलो बीज लगाया गया था। मिर्च में वरदान किस्म का बीज बेहतर माना जाता है। सोनू ने यही बीज लगाया है। एक बीघा के लिए 200 ग्राम बीज की जरूरत होती है, जबकि पूरे खेत में 500 ग्राम बीज लगाया है। बैंगन की देसी किस्म लगाते हैं।

बैंगन में पोषक तत्व

- फाइबर: बैंगन फाइबर का अच्छा स्रोत है। फाइबर पाचन तंत्र के लिए बेहतर होता है। साथ ही, यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है।
- पोटैशियम- बैंगन में पोटैशियम होता है, जो रक्तचाप कम करने में मदद करता है।
- विटामिन बी कॉम्प्लेक्स: बैंगन में बी5 और बी6 जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। विशेष रूप से, बी-6 मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषण में भाग लेता है। जैसे कि सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और डोपामाइन, जो चिंता और भय को नियंत्रित करते हैं।
- विटामिन सी: बैंगन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जो त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

-नवनिर्मित संरचनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया

रीवा में बसामन मामा गौवंश वन्य विहार अपनी पहचान स्थापित करेगा

रीवा। जागत गांव हमार

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसम्पर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि बसामन मामा गौवंश वन्य विहार देश व प्रदेश में अपनी पहचान स्थापित करेगा। आदर्श वन्य विहार के तौर पर स्थापित होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वस्ति वाचन के उद्घोष के साथ चित्रकूट नयागांव आश्रम के महंत युवराज बद्री प्रपन्नाचार्य एवं मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद सहित अन्य संतों की उपस्थिति में शुक्ल ने बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में 10 करोड 38 लाख 86 हजार रुपए की लागत से नवनिर्मित नवीन संरचनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले सामुदायिक भवन का भूमिपूजन भी संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि संतजनों की उपस्थिति में आज यह पवित्र कार्य संपन्न हुआ। बसामन मामा गौवंश वन्य विहार के भूमिपूजन में वर्ष 2018 में संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। आज इसके लोकार्पण के साथ ही वर्ष 2018 से प्रारंभ यज्ञ का समापन हुआ है और एक उपलब्धि जुड़ गई है। इस वन्य विहार की प्रशंसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में गौ माता के गोबर एवं मूत्र से बनाए गए उत्पादों से इसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा तथा इसकी मार्केटिंग कर इसे विस्तारित किया जाएगा और अन्य गौशालाओं को भी मदद दी जाएगी। बसामन मामा की कृपा से स्थापित इस गौवंश वन्य विहार में 10 हजार से अधिक गौवंश संरक्षित व संवर्धित किए जाएंगे। अब बेसहारा गौवंश से किसानों की खेती का नुकसान नहीं होगा तथा सड़कों में बैठने वाले गौवंश दुर्घटना के शिकार भी नहीं होंगे।

कृषि अनुसंधान केन्द्र बनाने के प्रयास होंगे | मंत्री ने कहा कि रीवा जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में इसी प्रकार के गौवंश वन्य विहार बनाए जाने का प्रस्ताव है। गौवंश वन्य विहार में कृषि अनुसंधान केन्द्र बनाने के प्रयास होंगे। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा से विकास के अन्य कार्य बेहतर ढंग से होंगे। गौवंश वन्य विहार की स्थापना में बसामन मामा व संतों एवं गुरूओं का आशीर्वाद मिला है। रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 400 टंकियों का निर्माण कर हर घर में नल से पानी पहुंचाए जाने का कार्य प्रगति पर है। गौवंश वन्य विहार में भी सैम्प वेल में पानी डाला जाएगा और गौ माताओं को फिल्टर पानी मिलेगा।

गौशालाएं आत्मनिर्भर बन रही | मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने कहा कि गौवंश की विरासत को बचाने के लिए यह वन्य विहार एक उदाहरण है जिसमें सभी विभागों के समन्वय से कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से नवीन प्रयोग हो रहे हैं जिनसे गौशालाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने गौशालाओं में आमजनों की भागीदारी की भी अपेक्षा की। स्वामी ने कहा कि यह गौवंश वन्य विहार एक आदर्श केन्द्र बना है. इससे अन्य गौवंश वन्य विहार भी प्रेरणा लेंगे।

आदर्श गौ संरक्षण केन्द्र बनेगा

सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि गौवंश वन्य विहार के विकास के साथ ही सेमरिया क्षेत्र का विकास होता रहा। बसामन मामा व गौ माता की कृपा से सेमरिया क्षेत्र में 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए। सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना से इस क्षेत्र की एक-एक इंच भूमि सिंचित होगी। यह गौवंश वन्य विहार आर्थिक तौर पर सशक्त व आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश का आदर्श गौ संरक्षण व संवर्धन का केन्द्र बनेगा। उन्होंने मांग की कि गौवंश वन्य विहार में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना कराई जाए।

जैविक खाद इकाई शुरू

इस अवसर पर गोबर गैस यूनिट, यज्ञशाला निर्माण, रेस्टहाउस निर्माण, पशु चिकित्सालय, पंप हाउस, गौशाला में गेट निर्माण, रपटा एवं चेक डैम निर्माण, पीपीसी पेवर ब्लॉक, जैविक खाद इकाई, भूसा शेड एवं गौ शेड निर्माण के साथ ही नर्सरी व पीसीसी रोड़ के 1038.86 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण हुआ। उल्लेखनीय है कि गौशाला में संलग्न 400 महिला सदस्यों द्वारा अभी तक लगभग 10.32 लाख की सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है।

-केन-बेतवा लिंक परियोजना से बदल जाएगी सूखे बुंदेलखंड की पहचान

केन-बेतवा लिंक! मप्र को 60 और यूपी को 40 फीदसी मिलेगा पानी

-किसान बोले- पानी देख लिया तो खुशी से मर पाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहले केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का भूमिपूजन टल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच अक्टूबर को जबलपुर से पहले छतरपुर आकर इस प्रोजेक्ट का भूमिपूजन करने वाले थे, लेकिन फॉरेस्ट क्लीयरेंस न मिलने से आखिरी मौके पर इसे आगे बढ़ाना पड़ा। हालांकि, इस प्रोजेक्ट की चर्चा के बाद बुंदेलखंड के किसानों की उम्मीदें फिर जाग गई हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने तो पूरी जिंदगी सूखे खेतों के साथ गुजार दी, लेकिन यदि नहर में पानी आ जाए तो वे सुकून के साथ मर पाएंगे। उनके बच्चों को रोजी-रोटी के लिए दिल्ली-मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। '**जागत गांव हमार**' ने बुंदेलखंड के अलग-अलग हिस्सों में जाकर यह समझने की कोशिश की कि आखिर किसानों को केन-बेतवा का कितना इंतजार है। किस तरह से यह परियोजना भीषण जल समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगी।

भरी दोपहरी में खेत में पूरे परिवार के साथ तिल की फसल काट रहे पप्पू श्रीवास इसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। जिंदगी के 50 साल उन्होंने अपना खेत रहते हुए भी दूसरे राज्यों में मजदूरों की तरह काटे हैं। सामने दूर-दूर तक खाली पड़े खेतों को दिखाते हुए वे कहते हैं, बस जीते-जी इन खेतों में नहर का पानी आता देख लूं। कम से कम इस खुशी से मर पाऊंगा कि पूरी जिंदगी हमें जो तकलीफ हुई, वो हमारे बच्चों को नहीं होगी। पप्पू जैसे किसानों की यह उम्मीद केन-बेतवा लिंक परियोजना है। कागजों पर 18 साल पहले ही आ चुकी केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सारी स्वीकृतियां अंतिम चरण में हैं। इस परियोजना से पूरे बुंदेलखंड की प्यास बुझ सकेगी। इससे मप्र के 9 जिलों में भी सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर होगी।

केन-बेतवा नहर बन जाए तो आनंद ही आनंद

केन-बेतवा लिंक कैनाल बनने से मुख्य तौर पर मध्यप्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ जिले को सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसलिए हम सबसे पहले छतरपुर की ओर निकले। हम हमां गांव गए। इस गांव के 2-3 किलोमीटर दूर से ही केन-बेतवा लिंक कैनाल गुजरेगी। यहां के पप्पू श्रीवास ने बताया कि हमारे पास 20 एकड़ जमीन है। खेती बमुश्किल 10 एकड़ में भी नहीं कर पाता हूं। जब पानी ही नहीं है तो खेती कैसे होगी। हम बाहर जाकर दूसरों के यहां मजदूरी करते हैं। बस चाहता हूं केन-बेतवा नहर में अब और देरी ना हो, ताकि हमारे बीस एकड़ में फसल लहलहा जाए।

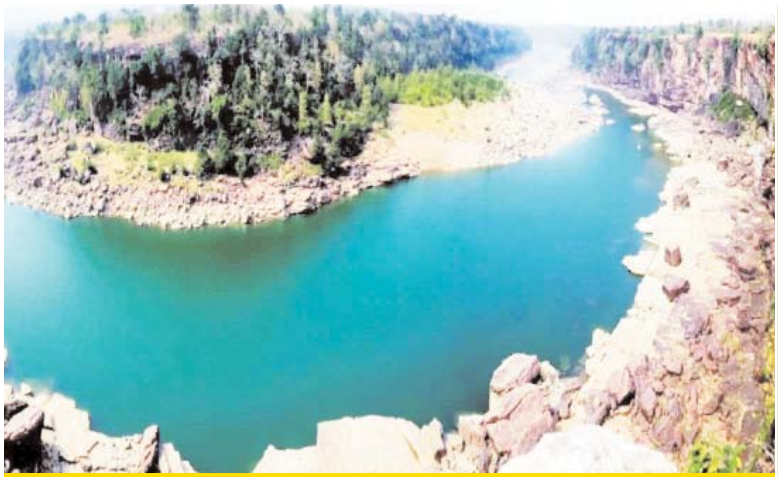

बुंदेलखंड में पलायन दर 50 से 70 फीसदी

बुंदेलखंड में पलायन दर 50 से 70 फीसदी तक है। पप्पू श्रीवास के 26 वर्षीय बेटे मुकेश बीते 5 साल से मजदूरी करने दिल्ली जाते हैं। इन दिनों वो छुट्टी पर आए हैं। मुकेश बताते हैं कि अगर यहां पानी की समस्या नहीं रहती तो अपने घर में रहकर खेती करके दिल्ली से भी ज्यादा कमा लेता। मगर हमें तो पीने का पानी लाने भी दो-तीन किमी दूर तक जाना पड़ता है। केन-बेतवा परियोजना को मेरे और मेरे जैसे कई परिवार बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। पानी की समस्या खत्म हो गई तो अगली पीढ़ी पलायन ना करके अपने गांव में ही खेती करेगी।

प्रोजेक्ट पर एक नजर

केन और बेतवा बुंदेलखंड की दो सबसे बड़ी नदियां हैं, जो दो अलग-अलग छोरों पर बहती हैं। यमुना की इन दो सहायक नदियों को एक लिंक कैनाल से जोड़ने की योजना है। 44 हजार 65 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इससे पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2003 में इस योजना की स्वीकृति दी थी। नेशनल परस्पेक्टिव प्लान ने इस परियोजना के तहत देश की 30 नदियों को जोड़कर पूरे भारत में समान रूप से पानी वितरित करने की परिकल्पना की थी। इसके तहत हिमालय की 14 नदियां और 16 प्रायद्वीपीय नदियों को लिंक कैनाल से जोड़ने की योजना है। इस योजना को धरातल पर लाने के लिए 1982 में नेशनल वाटर डवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया था। इसकी जिम्मेदारी नदियों के जोड़ने के लिए हर एसेसमेंट को पूरा करना था। 2002 में आई नेशनल वाटर पॉलिसी में इसे कृषि, औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि जहां पानी की उपलब्धता ज्यादा है, इस माध्यम का उपयोग कर कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसका पहला प्रयोग केन और बेतवा नदी को जोड़ने का था। इसे देखते हुए पहली बार 2010 में नेशनल वाटर डवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी पहली डीपीआर लेकर आया। 23 मार्च 2021 को सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इन दो नदियों को जोड़ने के लिए दोनों राज्यों के बीच हुए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक कहा था।

मध्यप्रदेश को होगा जबरदस्त फायदा

केन और बेतवा के जुड़ने से मध्यप्रदेश के 9 जिलों को सीधा फायदा होगा। इसमें मुख्य रूप से छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और सागर हैं। इनके अलावा दमोह, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन में भी पेयजल और सिंचाई की समस्या से निजात मिलेगी। इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसमें मध्यप्रदेश के 9 जिलों की 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अलावा इस परियोजना से बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, जिसमें मध्यप्रदेश का हिस्सा 41 लाख होगा। दोनों नदियों को लिंक करने के दौरान में केन नदी पर एक बड़ा डैम बनाया जाएगा, जिसपर 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन प्रस्तावित है।

डैम और नहर बनने में लगेंगे आठ साल

केन और बेतवा को जोड़ने की प्रक्रिया दो फेज में पूरी होगी। पहले फेज में केन नदी पर एक बड़ा डैम और केन बेतवा के बीच 219 किमी का लिंक कैनाल बनाया जाएगा। इसमें 2 किमी का एक टनल भी होगा। केन नदी के किनारे दौधन गांव में 77 मीटर ऊंचा डैम बनाया जाएगा, जिसका नाम दौधन डैम होगा। यहीं से 219 किमी लंबी लिंक कैनाल शुरू होगी जो छतरपुर, टीकमगढ़ और महोबा के रास्ते झांसी में बेतवा नदी से मिल जाएगी। लिंक कैनाल के एक तरफ मध्यप्रदेश के दो जिले छतरपुर और टीकमगढ़ हैं तो दूसरी तरफ यूपी के महोबा और झांसी। दूसरे फेज में बेतवा नदी के कम पानी वाले बेसिन में पानी की कमी को पूरा करने के लिए तीन और डैम बनाए जाएंगे। पहला डैम बेतवा पर लोअर ओर, दूसरा डैम ओर नदी पर शिवपुरी में और तीसरा डैम बीना कॉम्प्लेक्स सागर में बनाया जाएगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर छतरपुर में पदस्थापित एसडीओ विवेक मित्तल के अनुसार दो स्टेज में डैम का क्लियरेंस मिलना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉयमेंट एंड फॉरेस्ट से स्टेज वन का एनवॉयमेंट क्लियरेंस मिल चुका है। कुछ जरूरी शर्तें पूरी करने के बाद जल्द ही फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल जाएगा। 31 अक्टूबर तक बिडिंग की प्रोसेस खत्म हो जाएगी और उसके बाद डैम बनने का काम शुरू हो सकता है। कैनाल के लिए दिसंबर-जनवरी से जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। फिर इसके मुआवजे और बिडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।

नौ हजार हेक्टेयर तक होगा पानी का फैलाव

छतरपुर जिले के दौधन गांव जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है, वहां डैम बनाकर केन नदी के पानी को रोका जाएगा। केन नदी पर मौजूदा गंगऊ वियर से 2.5 किलोमीटर ऊपर की ओर दौधन डैम बनाया जाएगा। मृत जलाशय की अवस्था 240 मीटर और पूर्ण जलाशय की 280 मीटर होगी। पानी के सकल भंडारण के समय इसका फैलाव 9 हजार हेक्टेयर भूमि पर होगा, जिसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर और बफर एरिया सहित 6 हजार 17 हेक्टेयर जंगल सबमर्ज हो जाएगा। यानी कि डूब क्षेत्र में आ जाएगा। पानी का फैलाव इससे लगे टेरिटोरियल फॉरेस्ट तक भी होगा। इससे कोर और बफर एरिया के 22 गांव भी प्रभावित होंगे। मृत अवस्था में पानी का स्टोरेज 169 एमसीएम और फुल कैपिसिटी में इसकी सकल भंडारण क्षमता 2853 एमसीएम होगी।

अंतिम क्लीयरेंस में दो परेशानियां

तीन अक्टूबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉयमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा। इसमें मुख्य रूप से दो शर्तें हैं जिसकी वजह से इस प्रॉजेक्ट को अंतिम अप्रूवल मिलने का इंतजार है। पहली शर्त कि राज्य सरकार पन्ना टाइगर रिजर्व को जल्द से जल्द 6809 हेक्टेयर राजस्व की जमीन फॉरेस्ट लैंड के लिए दे। चूंकि पन्ना टाइगर रिजर्व का 6017 हेक्टेयर जंगल डूब रहा है, इसलिए 6089 हेक्टेयर में से इतने हेक्टेयर जमीन पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए नोटिफाई किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए राज्य सरकार को 1298 हेक्टेयर दिया जाना अभी बाकी है। अंतिम स्वीकृति से 6 महीने पहले इन सारे एरिया को पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए नोटिफाई करने की शर्त है। इसके अलावा नौरादेही, राणी दुर्गावती और रानीपुर अभियारण्य को भी इससे जोड़ने की शर्त है। दूसरी मुख्य शर्त ये है कि दौधन डैम पर प्रस्तावित बिजलीघर को कहीं और शिफ्ट किया जाए। जंगल में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भी कुछ और शर्तें हैं जिसके बाद ही इस परियोजना को अंतिम स्विकृति मिल सकती है।

पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा टकराव रहा

दौधन डैम में सालाना 6590 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर किया जाएगा, जिसमें मध्यप्रदेश को 2350 एमसीएम और उत्तर प्रदेश को 1700 एमसीएम पानी मिलेगा। दोनों राज्य की सरकारों में पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा टकराव रहा है। उत्तरप्रदेश हमेशा से ज्यादा पानी की डिमांड करता रहा है, लेकिन उसे खारिज किया जाता रहा है। द वायर की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि बिना किसी हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के बीच दोनों राज्यों के बीच यह हिस्सा बांट दिया गया, मगर अधिकारी इसे नकारते रहे। यह भी सच है कि भीषण गर्मी के दौरान या मानसून से पहले जब पानी का बहाव कम होता है, ऐसे मौसम में पानी के बंटवारे में अपने-अपने हिस्से पर दोनों राज्यों में कभी आम सहमति नहीं बन पाई थी।

पानी का इस्तेमाल कहां कितना होगा

दौधन जलाशय से 4543.52 एमसीएम पानी का इस्तेमाल घरेलू और औद्योगिक के साथ पर्यावरण के लिए उपयोग होना है। शेष 2035 एमसीएम में से 435 एमसीएम पानी का इस्तेमाल सलेहा लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत पन्ना और दमोह जिले में सिंचाई के लिए होगा। 1377 एमसीएम पानी केन बेतवा लिंक कैनाल में डायवर्ट किया जाएगा, जिसमें 220.77 एमसीएम का इस्तेमाल एक पंपिग स्टेशन पर होगा। अत्यधिक मानसून में 222 एमसीएम का इस्तेमाल नदी में स्पिल वाटर के रूप में होगा। 1010.51 एमसीएम पानी का इस्तेमाल कैनाल के रास्ते में आ रहे 1 लाख 94 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में होगा। 94.79 एमसीएम पानी इसी रास्ते में पीने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी

इस लिंक कैनाल से छतरपुर और टीकमगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश के दूर के जिले विदिशा या रायसेन तक पानी कैसे पहुंचेगा। क्या एक लिंक कैनाल पर्याप्त है। इसके जवाब में विवेक मित्तल बताते हैं कि इस परियोजना का सबसे बड़ा पार्ट दौधन डैम और लिंक कैनाल का निर्माण है। इस परियोजना के तहत ही बुंदेलखंड के अलग-अलग जिलों में 40-45 तालाबों का निर्माण होगा। इसके अलावा बरियारपुर पिकअप बियर, बरूआसागर बियर, परीछा बियर सबका रेनोवेशन होगा। इसके बाद दोनों राज्य की सरकार कई जलाशय और सब कैनाल भी बनाएगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि इसका फायदा बुंदेलखंड के हर सूखाग्रस्त क्षेत्र को मिले।

आलू उत्पादन की उन्नत तकनीक में तापमान का प्रभाव

» डॉ. संदीप कुमार शर्मा
मौसम वैज्ञानिक
» डॉ. राजेश सिंह, उद्यानिकी वैज्ञानिक
» डॉ. मृत्युंजय कुमार मिश्रा, तकनीकी
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा (म.प्र.)

आलू की वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है। और जैसा की हम जानते हैं आलू कंद मूल है तो कंद की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस सही रहता है। लंबी रातें एवं अच्छी धूप वाले छोटे दिन आलू की फसल के लिए लाभकारी रहते हैं। आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। चावल, गेहूँ, गन्ना के बाद क्षेत्रफल में आलू का चौथा स्थान है। आलू से प्रति इकाई क्षेत्रफल में अन्य फसलों (गेहूँ, धान एवं मूँगफली) की अपेक्षा अधिक उत्पादन मिलता है तथा प्रति हेक्टर आय भी अधिक मिलती है।

आलू समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती उपोष्णीय जलवायु की दशाओं में रबी के मौसम में की जाती है। सामान्य रूप से अच्छी खेती के लिए फसल अवधि के दौरान दिन का तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस तथा रात्रि का तापमान 4-15 डिग्री सैल्सियस होना चाहिए। फसल में कन्द बनते समय लगभग 18-20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम सर्वोत्तम होता है। लगभग 30 डिसे. से अधिक तापक्रम होने पर आलू की फसल में कन्द बनना बिलकुल बन्द हो जाता है।

भूमि एवं भूमि प्रबन्ध: आलू की फसल विभिन्न प्रकार की भूमि, जिसका पी.एच. मान 6 से 8 के मध्य हो, उगाई जा सकती है, बलुई दोमट तथा दोमट उचित जल निकास की भूमि उपयुक्त होती है। 3-4 जुताई डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से करें। वर्तमान में रोटावेटर से भी खेत की तैयारी शीघ्र व अच्छी हो जाती है। आलू की अच्छी फसल के लिए बोने से पहले पलेवा करना चाहिए। हरी खाद का प्रयोग न किया हो तो 15-30 टन प्रति है. सड़ी गोबर की खाद प्रयोग करने से जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जो कन्दों की पैदावार बढाने में सहायक होती है।

खाद तथा उर्वरक प्रबन्ध: सामान्य तौर पर 180 किग्रा0 नत्रजन, 80 किग्रा0 फास्फोरस तथा 100 किग्रा0 पोटाश की संस्तुति की जाती है। मृदा विश्लेषण के आधार पर मात्रा घट-बढ़ सकती है। 180:80:100 कि. नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश/है. की पूर्ति हेतु उर्वरकों के विभिन्न विकल्प हो सकते हैं

खाद तथा उर्वरक प्रबन्ध: मिट्टी परीक्षण की संस्तुति के अनुसार अथवा 25 किग्रा. जिंक सल्फेट एवं 50 किग्रा0 फेरस सल्फेट प्रति है. की दर से बुआई से पहले कम वाले क्षेत्रों में प्रयोग करना चाहिए तथा आवश्यक जिंक सल्फेट का छिड़काव भी किया जा सकता है।

बीज: बोने के लिए 30-55 मिमी. व्यास का अंकुरित आलू बीज का प्रयोग करना चाहिए। एक हेक्टेयर के लिए 30-35 कुन्तल बीज की आवश्यकता पड़ती है। प्रजातियों का चयन क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं बुआई के समय यथा अगेती फसल, मुख्य फसल अथवा पिछेती फसलों के अनुसार किया जाना उचित होता है।

बुआई का समय: सामान्यत: अगेती फसल की बुआई मध्य सितम्बर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक, मुख्य फसल की बुआई मध्य अक्टूबर के बाद हो जानी चाहिए।

बीज की बुआई: भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो, पलेवा करना आवश्यक होता है। बीज कन्दों को कूडों में बोया जाता है तथा मिट्टी से ढककर हल्की मेंड़ें बनाई जाती है।

खरपतवार नियन्त्रण: खरपतवार को नष्ट करने के लिए निराई-गुड़ाई आवश्यक है।

सिंचाई प्रबन्ध: पौधों की उचित वृद्धि एवं विकास तथा अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 7-10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि आलू की बुआई से पूर्व पलेवा नहीं किया गया है तो बुआई के 2-3 दिन के अन्दर हल्की सिंचाई करना अनिवार्य है। भूमि में नमी 15-30 प्रतिशत तक कम हो जाने पर सिंचाई करनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए अंकुरण से पूर्व बलुई दोमट व दोमट मृदाओं में बुआई के 8-10 दिन बाद तथ भारी मृदाओं में 10-12 दिन बाद पहली सिंचाई करें। अगर तापमान के अत्यधिक कम होने और पाला पड़ने की संभावना हो तो फसल में सिंचाई अवश्य करें। आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप से पानी के उपयोग की क्षमता में वृद्धि होती है। कूंड़ों में सिंचाई की अपेक्षा स्प्रिंकलर प्रणाली से 40 प्रतिशत तथा ड्रिप प्रणाली से 50 प्रतिशत पानी की बचत होती है, पैदावार भी 10-20 प्रतिशत वृद्धि होती है।

कीट एवं व्याधि रोकथाम: आलू को बहुत सी बीमारियों तथा कीट हानि पहुँचाते हैं।

पिछेता सुलझा (लेट ब्लाइट): यह आलू में फफूंद से लगने वाली एक भयानक बीमारी है। इस बीमारी का प्रकोप आलू की पत्ती, तने तथा कन्दों, सभी भागों पर होता है। जैसे ही मौसम बदली युक्त हो, तो इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। अत: तुरन्त ही सिंचाई बन्द कर दें। यदि आवश्यक हो तो बहुत हल्की सिंचाई ही करें तथा लक्षण दिखाई देने से पूर्व ही बीमारी की रोकथाम की लिए 0.20 प्रतिशत मैंकोजेब दवा के घोल का छिड़काव 8-10 दिन के अन्तराल पर करना चाहिए।

अगेता झुलसा: अगेता झुलसा बीमारी से पत्तियों और कन्द दोनों प्रभावित होते हैं। रोग अवरोधी किस्मों का चयन किया जाये। इस बीमारी की रोकथाम के लिए 0.3 प्र. कॉपर आक्सीक्लोराइड फफूँदनाशक के घोल का प्रयोग किया जाये।

आलू की पत्ती मुड़ने वाला रोग (पोटेटो लीफ रोल): यह एक वायरल बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए रोग रहित बीज बोना चाहिए तथा इस वायरस के वाहक एफिड की रोकथाम दैहिक कीटनाशक यथा फास्फोमिडान का 0.04 प्रतिशत घोल मिथाइलऑक्सीडिमीटान अथवा डाइमिथोएट का 0.1 प्रतिशत घोल बनाकर 1-2 छिड़काव दिसम्बर, जनवरी में करना चाहिए।

दीमक: दीमक का प्रकोप ज्यादातर अगेती फसल में होता है। इससे प्रभावित आलू के पौधों की पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है। अधिक प्रकोप की अवस्था में पत्तियों स्मंजीमतल हो जाती हैं तथा पत्तियों की निचली सतह पर तांबा के रंग जैसे धब्बे दिखायी पड़ते हैं। दीमक की रोकथाम के लिए डाइकोफाल 18.5 ई.सी. की 2 लीटर मात्रा प्रति है0 की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें तथा 7-10 दिन के अन्तराल पर पुन: दोहरायें।

आलू की खुदाई: अगेती फसल से अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए बुआई के 60-70 दिनों के उपरान्त कच्ची फसल की अवस्था में आलू की खुदाई की जा सकती है। फसल पकने पर आलू खुदाई का उत्तम समय मध्य फरवरी से मार्च द्वितीय सप्ताह तक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आने से पूर्व ही खुदाई पूर्ण कर लेना चाहिए।

अदरक तेरे रूप अनेक: पोषक व औषधीय गुण

» डॉ. रीता मिश्रा
» डॉ. संगीता द्विवेदी
-कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरैना, मध्य प्रदेश
-उपाधी पीजी महाविद्यालय, पीलीभीत, उप्र

अदरक गुणों की खान है। अदरक का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। भोजन के एक महत्वपूर्ण अंग और औषधि, दोनों रूपों में अदरक या सोंठ का प्रयोग होता है। विशिष्ट गुणों से भरपूर अदरक का इस्तेमाल कई बड़ी-छोटी बीमारियों में भी किया जाता है। औषधि के रूप में इसका प्रयोग गठिया, गर्दन व रीढ़ की हड्डियों की बीमारी (सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस) होने पर किया जाता है। जोड़ों की इन बीमारियों के अतिरिक्त भूख न लगना, अमीबिक पेचिश, खाँसी, जुकाम, दमा और शरीर में दर्द के साथ बुखार, कब्ज होना, कान में दर्द, उल्टियाँ होना, मोच आना, उदर शूल और मासिक धर्म में अनियमितता होना इन सब रोगों में भी अदरक (सोंठ) को दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिदिन बनाई जाने वाली सब्जियों में अदरक का उपयोग अच्छा होता है।

हमारे यहां अदरक का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। अदरक शरीर के कई रोगों से मुक्ति भी दिलाता है। इससे शरीर के होने वाले वात रोगों से मुक्ति मिलती है। अदरक का काढ़ा व चूर्ण बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक के कई फायदे हैं, जैसे-

पाचन तंत्र को मजबूती: अदरक खाने से पाचन प्रक्रिया अच्छी रहती है। है। अदरक कब्ज, पेट दर्द, पेट की ऐंठन, मरोड़ व गैस जैसी कई समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक होता है। यह अपच की समस्या को ठीक करने में भी मददगार होता है।

एंटी इन्फ्लामेट्री गुण: अदरक में एंटी इन्फ्लामेट्री (सूजन कम करने वाला) गुण मौजूद होता है। इस गुण के कारण अदरक कई प्रकार की बीमारियों में मददगार साबित होता है।

उल्टी व जी मिचलाने में आराम: उल्टी व जी मिचलाने की समस्या में अदरक का उपयोग कर राहत पाने में मदद मिलती है।

माइग्रेन के लिए: अदरक में दर्दनिवारक गुण मौजूद होते हैं। यही दर्दनिवारक गुण माइग्रेन की समस्या भी सहायक साबित होता है।

नियंत्रित कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर: अदरक में हाइपोटेंसिव (ब्लड प्रेशर कम करने वाला) प्रभाव पाया जाता है। अदरक का रस लिपिड को नियंत्रित करने के साथ ही बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। अत: अदरक का प्रयोग कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने में लाभप्रद होता है।

डायबिटीज नियंत्रण में सहायक: अदरक बढ़े हुए ब्लड शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ ही इन्सुलिन की सक्रियता को बढ़ाने का भी काम करता है। इस तरह यह डायबिटीज की समस्या में लाभप्रद होता है।

प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए: अदरक में एंटीऑक्सीडेंट (मुक्त कणों को नष्ट करने वाला) और एंटीइन्फ्लामेट्री (सूजन कम करने वाला) गुण पाया जाता है। इसमें इम्यूनोन्यूट्रीशन गुण भी मौजूद होता है। अदरक का सेवन कर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में भी मदद मिलती है।

अदरक का उपयोग: सामान्य रूप से दिन में 100 मिग्रा. से 2 ग्राम तक अदरक का सेवन किया जा सकता है। अदरक को विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा सकता है-

सब्जी में तड़का लगाने में, अदरक का अचार बनाकर, चाय में अदरक का प्रयोग, अदरक का चूर्ण (पाउडर) के रूप में प्रयोग।

अदरक को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के तरीके: अदरक को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए-

अदरक को हमेशा वायुरोधित डिब्बे या एयरटाइट पॉलीथीन में रखें। फ्रिज में अदरक को करीब एक हफ्ते के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अदरक को टुकडों में काटकर उसे फ्रीजर में जमा दें। इस तरीके से भी अदरक को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अचार या सोंठ बनाकर भी अदरक को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

सोंठ बनाने की विधि:

सामग्री: अदरक 100 ग्राम, नीबू का रस, आवश्यकता अनुसार। चूने का पानी आवश्यकतानुसार

विधि: सबसे पहले अदरक को साफ पानी से धो लें। अब इसकी ऊपरी परत को चाकू से छील लें तथा इसे 24 घंटे के

लिए पानी से भरे बर्तन में डालकर छोड़ दें। अदरक को पानी से निकालकर, नींबू का रस मिले पानी से अच्छे से धोएं। अब इसे चूने के पानी में डुबोकर छोड़ दें। इसे चूने के पानी में तब तक भीगने दें, जब तक अदरक पर चूने की सफेद परत न आ जाएं। अब इसे चूने के पानी से निकाल कर धूप में सूखने के लिए छोड़ दें। अच्छी तरह सूख जाने के बाद टाट से रगड़कर इस पर बचे हुए छिलके को भी अलग कर दें। अब सोंठ को उपयोग कर सकते हैं तथा संग्रहित करके भी रख सकते हैं।

अदरक का अचार

सामग्री: अदरक 100 ग्राम, नीबू 100 ग्राम, नमक 10 ग्राम, काली मिर्च पाउडर 3 ग्राम, हींग 2 ग्राम, काला नमक 5 ग्राम, जीरा 3 ग्राम (भुना हुआ)

विधि: बिना रेशे का अदरक को छील लें और साफ पानी से धोकर सुखा लें। अब अदरक को छोटे व पतले -पतले टुकड़ों में काट लें। नींबू को धोकर उनका रस निकाल लें। अदरक के टुकड़ों में नीबू का रस, सफेद नमक, काला नमक, हींग, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च पाउडर मिला दें। सभी को अच्छी तरह मिलाकर कांच के मर्तबान में भरकर, अच्छी तरह ढक्कन बन्द करके 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख दें। हर दूसरे दिन अचार को हिला कर नीबू के रस को ऊपर नीचे करते रहें। 8 से 10 दिन में अदरक का स्वादिष्ट अचार बन कर तैयार हो जाता है। अदरक के अचार को 6 महीने तक संग्रहित करके रखा जा सकता है ।

जलवायु परिवर्तन: बढ़ सकती हैं सिक्किम जैसी आपदाएं

उत्तरी सिक्किम में दक्षिण ल्होनक झील के टूटने यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड से जुड़े कई सवाल हैं, वैज्ञानिक जिनके जवाब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर एकमत हैं कि इस प्राकृतिक आपदा की एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है, और भविष्य में ग्लेशियल झीलों के बनने और टूटने का खतरा बड़ा हो रहा है। ल्होनक झील समुद्र तल से करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर है। आमतौर पर 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बारिश नहीं बल्कि बर्फबारी होती है। तो क्या ल्होनक झील के ऊपर बादल फटने की घटना हुई, जिससे झील में अचानक पानी की मात्रा बढ़ी?

सितंबर, 2023 का औसत वैश्विक तापमान 1991-2020 के औसत से 0.93 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसरो का सैटेलाइट डाटा दिखाता है कि सितंबर महीने में ल्होनक झील का आकार बढ़ा है। तो क्या ग्लेशियर के पिघलने से झील में पानी बढ़ा?

पिछले एक साल में हिमालयी क्षेत्र में 3 बड़े भूकंप आ चुके हैं। 3 अक्टूबर की रात पश्चिमी नेपाल और पूर्वी उत्तराखंड में 6 तीव्रता के भूकंप का असर क्या करीब 700 किलोमीटर दूर सिक्किम हिमालयी क्षेत्र पर भी रहा?

क्या हिमालयी ग्लेशियर क्षेत्र में खतरे के लिहाज से संवेदनशील मानी जाने वाली प्रोग्लेशियल झीलों (जिनके तटबंध मोरेन यानी ढीली धूल-मिट्टी से बनते हैं) की मॉनिटरिंग और नुकसान से बचाव के लिए अर्ली वॉर्निंग अलर्ट सिस्टम विकसित है?

इसरो की सेटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि 17 सितंबर 2023 को ल्होनक झील का आकार 162.7 हेक्टेअर था, 28 सितंबर को झील बढ़कर 167.5 हेक्टेअर में फैल गई और 4 अक्टूबर को झील टूटने के बाद उसका आकार 60.4 हेक्टेअर ही दिखाई दे रहा है। यानी उस दौरान झील के 100 हेक्टेअर से अधिक क्षेत्र से पानी निकलकर सीधा नीचे की ओर आया।

ल्होनक झील भी मोरेन तटबंध से बनी है। झील का पानी करीब 50 किलोमीटर नीचे तीस्ता नदी पर बने चुंगथांग हाइड्रो बांध तक आया। ल्होनक झील का आकार इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की झील से 6 गुना से भी अधिक है। उस समय वहां बादल फटने और अत्यधिक भारी बारिश की भी सूचना है। बांध की झील पानी के इस दबाव को झेल नहीं सकी जिससे डैम टूट गया और भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर आगे बढ़ा। मौसम विभाग की सूचना बताती है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में गर्मी बहुत ज्यादा थी। एक अनुमान यह है कि ग्लेशियर पिघलने की वजह से ल्होनक झील में पानी बढ़ा होगा। फिर बादल फटने और भारी बारिश की रिपोर्ट है। झील में क्षमता से अधिक पानी भरने की वजह से उसके मोरेन तटबंध टूट गए और झील टूट गई। जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत सी मौसमी अनियमितताएं हो रही हैं। वाडिया संस्थान मौसमी घटनाओं का अध्ययन नहीं करता। लेकिन समुद्रतल से 4500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी होती है बारिश नहीं। करीब 5200 मीटर ऊंचाई पर ल्होनक झील के ऊपर बादल फटने की घटना की भी जांच की जरूरत है। हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन भूकंपों ने पहले से संवेदनशील ल्होनक झील को उत्प्रेरित किया और क्या भूगर्भीय वजहों के चलते भी झील टूट सकती है।

कॉलेज की स्थापना पर करीब 160 करोड़ रुपए की लागत आएगी

फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूलों की खेती और भू-निर्माण, पौध संरक्षण, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बुनियादी विज्ञान आदि जैसे विभिन्न विभाग होंगे

पोरसा में लगभग 300 एकड़ भूमि का आवंटन भी कर दिया गया

मुरैना में खुलेगा हार्टिकल्चर कालेज

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तहत मुरैना जिले में हार्टिकल्चर कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तहसील पोरसा, जिला मुरैना में लगभग 300 एकड़ भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है। इस कॉलेज की स्थापना पर करीब 160 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। श्री तोमर ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और मप्र शासन का इसके लिए आभार प्रकट किया है।

इस अंचल में यह कालेज अपनी तरह का पहला कालेज होगा एवं इसमें स्नातक स्तर की पढ़ाई होगी, जिसमें फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूलों की खेती और भू-निर्माण, पौध संरक्षण, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बुनियादी विज्ञान आदि विभिन्न विभाग होंगे। इस कॉलेज के माध्यम से हार्टिकल्चर संबंधी अनुसंधान कार्यों को भी गति मिलेगी। साथ ही नए रोजगार भी सृजित होंगे और क्षेत्र के किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी यह कालेज सहायक होगा। चंबल-ग्वालियर क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर के प्रयासों से इस तरह एक के बाद एक अनेक सौगातें मिली है।

मुरैना की पहचान है कृषि, बागवानी और डेयरी

मुरैना मध्य भारत के पठार व कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बुंदेलखंड ऊपरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुरैना जिले की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान है। जिले में कृषि, बागवानी एवं डेयरी मुख्य व्यवसाय है। यहां बागवानी फसलों के अंतर्गत अमरूद, नींबू, आम जैसे फल तथा आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा आदि सब्जियां उगाई जाती हैं। मुरैना जिले में धनिया, अदरक, हल्दी, मिर्च, फनल, लहसुन जैसे विभिन्न मसालों के साथ-साथ गेंदा, गुलाब एवं गिलार्डिया जैसे फूलों की भी खेती की जाती है। मुरैना जिला विभिन्न फलों, सब्जियों एवं फूलों के बड़े उत्पादक के रूप में उभर रहा है। यद्यपि क्षेत्र में हाल के दशक में बागवानी फसलों की खेती अत्यधिक लाभकारी उद्यम के रूप में उभरी है, फिर भी यह जिले में सकल फसल क्षेत्र का करीब 2.5 प्रतिशत ही है, इसलिए प्रस्तावित कॉलेज न केवल मुरैना जिले, बल्कि चंबल-ग्वालियर क्षेत्र की समग्र प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मील का पत्थर साबित होगा।

बकरी पालन में असल मुनाफा बकरी के बच्चों से

सर्दियों में ऐसे करें बकरी के बच्चों की देखभाल, कम होगी मृत्यु दर

भोपाल। जागत गांव हमार

गोट एक्सपर्ट की मानें तो जब एक बकरी बच्चा देती है तो वो पशुपालक का मुनाफा होता है। उसी बच्चे को निरोगी रख पाल पोसकर जब बड़ा करेंगे तो वो मुनाफा उतना ही मोटा होता जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसका ख्याल रखा जाए और तमाम तरह की बीमारियों समेत मौसम से बचाया जाए।

बकरी पालन में असल मुनाफा बकरी के बच्चों से होता है। सालभर जितने बच्चे मिलेंगे उतना ही मोटा मुनाफा होगा। ये बकरी पालन में मुनाफे की बुनियाद भी होते हैं। लेकिन बकरी के बच्चे मुनाफे में तब बदलते हैं जब उनकी मृत्यु दर को कम या फिर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (सीआईआरजी), मथुरा के साइंटिस्ट की मानें तो मृत्यु दर कम करने की तैयारी बकरी के गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है। साथ ही बच्चा पैदा होने के कम से कम 15 दिन तक खास देखभाल करनी होती है। बकरी के बाड़े में भी खास तैयारी करनी होती है। बच्चे के खानपान का भी ख्याल रखना होता है। ये सब करने से ही बच्चे में बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा होती है। अगर इस सब का पालन किया तो फिर सर्दी के मौसम में बच्चे ठंड से बार-बार बीमार नहीं पड़ेंगे।

60 दिन की खास देखभाल से कम होती है मृत्यु दर

सीआईआरजी के साइंटिस्ट डॉ. गोपाल दास ने किसान तक को बताया कि बकरी का गर्भकाल पांच महीने का होता है। आखिरी के 45 दिन बकरी के खानपान में हरा चारा, सूखा चारा और दाना शामिल होना चाहिए। इसका फायदा बकरी के होने वाले बच्चे को भी मिलेगा। बच्चे हैल्थी होंगे। बीमारी से लड़ सकेंगे। बकरी दूध भी ज्यादा देगी। इससे बच्चों को भी भरपूर दूध पीने को मिलेगा। बच्चा देने के तीन-चार दिन तक बकरी जो कोलस्ट्रम यानि खीज वाला दूध देती है। इस दूध में चार गुना तक प्रोटीन होता है। साथ ही एक खास इम्यूनोग्लोबीलिन प्रोटीन भी होता है, जो बच्चों को बीमारी से लड़ने की ताकत देता है।कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बकरी बच्चा देने के बाद उसे अपना दूध नहीं पिलाती है। ऐसे में बच्चे को उस दूसरी बकरी का दूध भी पिलाया जा सकता है जिसने उसी के आसपास बच्चा दिया हो। जन्म के करीब पांच-छह दिन तक बकरी और बच्चे को दूसरी बकरियों के झुंड से अलग अकेले में रखें। इससे होगा ये कि बकरी अपने बच्चे को ठीक तरह से पहचान लेगी। बच्चे को पहले 15 दिन सिर्फ बकरी के दूध पर ही रखें। बच्चे मिट्टी ना खाएं इसके लिए उनके आसपास हमेशा लाहौरी (सैंधा) नमक की डेली रखें।

सर्दियों में जरूर करें ये खास काम

साइंटिस्ट डॉ. गोपाल दास ने बताया कि सर्दी के मौसम में दो महीने तक के बच्चों की खास देखभाल बहुत जरूरी हो जाती है। क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चों को निमोनिया जकड़ लेता है। निमोनिया इतना खतरनाक हो जाता है कि बच्चों की जान तक ले लेता है। इसलिए बच्चों को ठंड से बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए ठंड का मौसम शुरू होते ही बच्चों को ठंडी हवा से बचाएं। शेड को तिरपाल या जूट की बोरी से चारों तरफ से ढक दें। जमीन पर भी सूखी घास बिछा दें। समय-समय पर घास को बदलते रहें, क्यों कि बच्चों के यूरिन से घास गीली हो जाती है। शेड में डेली वाले चूने का छिड़काव करें। चूना गर्मी पैदा करता है। साथ ही चूना छिड़कने से शेड में कीटाणु भी मर जाते हैं। 15 दिन के बाद बच्चों को दाना खिलाना शुरू कर दें।

अनुशंसित फफूंदनाशक से शोधन जरूर करें

फूलगोभी की उन्नत किस्में, किसानों को कम समय में दिलाएंगी ज्यादा फायदा

भोपाल। फूलगोभी की खेती से किसान कम समय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं. मालूम हो कि फूलगोभी की खेती किसान हर एक सीजन में कर सकते हैं। वहीं लोगों के द्वारा फूल गोभी का इस्तेमाल सब्जी, सूप और आचार आदि बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि इस सब्जी में विटामिन-बी की मात्रा के साथ प्रोटीन भी अन्य सब्जियों से कहीं अधिक पाया जाता है। यही वजह है कि बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है। वहीं फूलगोभी की खेती के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। ध्यान रहे कि फूलगोभी की फसल में रोग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके बचाव के लिए बीजों की बुवाई से पहले ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित फफूंदनाशक से शोधन जरूर करें।

फूलगोभी की उन्नत किस्में

- आईसीएआर, पूसा के वैज्ञानिकों ने किसानों को फूलगोभी की खेती से किसी भी सीजन में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कुछ बेहतरीन किस्मों को विकसित किया है, जिनमें पूसा अश्विनी, पूसा मेघना, पूसा कार्तिक और पूसा कार्तिक शंकर आदि शामिल हैं।
- वहीं फूल गोभी की अन्य अगेती किस्मों में- पूसा दिपाली, अर्ली कुवारी, अर्ली पटना, पन्त गोभी- 2, पन्त गोभी- 3, पूसा कार्तिक, पूसा अर्ली सेन्थेटिक, पटना अगेती, सेलेक्सन 327 और सेलेक्सन 328 आदि शामिल हैं।
- इसके अलावा फूलगोभी की पछेती किस्मों में- पूसा स्नोबाल-1, पूसा स्नोबाल-2, पूसा स्नोबॉल-16 आदि शामिल हैं।
- फूलगोभी की मध्यम किस्मों में- पंत सुभ्रा, पूसा सुभ्रा, पूसा सिंथेटिक, पूसा अगहनी उयर पूसा स्नोबॉल आदि शामिल हैं।

फूलगोभी की खेती के लिए जरूरी बातें

फूलगोभी की खेती के लिए आपको पहले खेत को समतल बनाएं, ताकि मिट्टी जुताई योग्य बन जाए। फिर आप जुताई दो बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद खेत में दो बार कल्टीवेटर चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 के मध्य होना चाहिए। फूलगोभी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। जिस मिट्टी में जैविक खाद की मात्रा अधिक हो वह फूलगोभी की उपज के लिए बेहद अच्छी होती है।

औषधीय गुणों की खान है महोबा का देसावर पान

जीआई टैग ने देसावर पान को दिलाई नई पहचान, कई देशों में है इसकी डिमांड

छतरपुर। जागत गांव हमार

उत्तर प्रदेश के महोबा का पान सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक इसकी पहचान है। एक समय था कि महोबा में अधिकांश लोग पान का ही व्यवसाय करते थे। करीब 2000 से अधिक लोग पान के कारोबार से अपना जीवन-यापन करते थे। महोबा क्षेत्र में करीब 600 एकड़ में सिर्फ पान की खेती होती थी। हम आपको बता दें कि पान की खेती अन्य फसलों के मुकाबले काफी ही संवेदनशीन है। पान की खेती करने वक्त इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

पहचान खत्म होने का मंडरा रहा था खतरा- महोबा के देसावर पर को देश-विदेशों तक कभी किसी समय में डिमांड थी। बीच में इसकी पहचान धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पर था, लेकिन देसावर पान को जीआईटैग टैग मिलने के बाद फिर से इसे एक नई पहचान मिली है। साथ ही महोबा के किसानों के चेहरे फिर से खिल उठे हैं। ऐसे में आइए आज जानते हैं महोबा के देसावर पान की डिमांड कई देशों में मोहबा के देसावर पान का डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में है। देसावर पान का स्वाद बाकी पान के पत्ते से काफी अलग होता है जिसे खाने की चाहत सभी रखते हैं। देसावर पान की डिमांड कनाडा, पाकिस्तान, लंदन, श्रीलंका। जापान आदि देशों से है। सभी देश के लोग काफी इस पान को पसंद करते हैं।

सरकार करती थी मदद

1984 के आसपास 300 पान किसानों को खाद्य एवं रसद मंत्री ने प्रति माह 17-17 लीटर मिट्टी का तेल देने के लिए सरकार ने योजना बनाई थी। जिससे किसान पान के फसलों की सिंचाई कर सकें। लेकिन धीरे-धीरे 200 पान किसानों के परमिट निरस्त कर दिए गए। सिंचाई के लिए मिट्टी का तेल न मिलने से किसानों को महंगा डीजल खरीदना पड़ रहा था। पान की खेती की लागत बढ़ने और आमदनी कम होने से बड़ी संख्या में किसानों ने पान की खेती से मुंह मोड़ लिया। लेकिन देसावार पान को जीआई टैग मिलने के बाद किसानों के चेहरे फिर से खिल उठे हैं।

औषधीय गुणों का खजाना है देसावर पान

पान के पत्तों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, लौह, आयोडीन और पोटैशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। पान प्राचीनकाल से ही आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी के रूप में जाना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीडायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी-कैंसर, एंटी-अल्सर जैसे औषधीय गुण पाए जाते हैं। जिसके चबाकर रस लेने से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं।

श्रीअन्न की उन्नत किस्में, जो देंगी ज्यादा उपज, किसान हो सकते हैं मालामाल

भोपाल। भारत में इन दिनों मिलेट्स के उत्पादन और इसकी खपत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश की अलग-अलग संस्थानों के द्वारा मिलेट्स को लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन कायक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि मोटे अनाजों की खपत में बढ़ोतरी हो सके और इसकी पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं खरीफ फसलों में श्री अन्न एक महत्वपूर्ण फसल है। इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा तो होती ही है और साथ ही देश के किसान कम वर्षा वाले स्थान से भी इसकी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि श्री अन्न यानी मोटे अनाजों की उन्नत किस्मों और किसानों को इसकी खेती के प्रति जागरूक करने के लिए पूसा संस्थान में इसकी कई तरह के अलग-अलग किस्मों को लगाया गया है।

पूसा संस्थान ने लगाई मिलेट्स की उन्नत किस्में- पूसा संस्थान के डॉ. सुमेर पाल सिंह के मुताबिक, लोगों व किसानों को मिलेट्स की अधिक से अधिक जानकारी मिल सकें और देश ही नहीं बल्कि विदेशों के बाजार में भी इसकी मांग अधिक बढ़ सके। इसी क्रम में पूसा संस्थान ने मिलेट्स की 9 किस्मों को लगाया हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। बाजरा, ज्वार, रागी, फॉक्सटेल बाजरा, प्रोसो बाजरा, बार्नयार्ड बाजरा, लिटल बाजरा, कोदो बाजरा और ब्राउनटॉप बाजरा है।

मिलेट्स की उन्नत किस्में

- बाजरा की दो किस्में- पूसा 1201 किस्म और दूसरी किस्म पूसा 1801
- रागी की दो किस्में- सीएफएमवी-1 और जीपीयू 28 किस्म
- गौरघुम की उन्नत किस्में- सीएसवी 15 किस्म और सीएसएच 41 किस्म
- फॉक्सटेल की उन्नत किस्में- एसआईए 3085 और एसआईए 3156 किस्म
- बार्नयार्ड की उन्नत किस्में- डीएचबीएम 93-2 और डीएचबीएम 93-3 किस्म
- लिटल बाजरा की उन्नत किस्में- ओएलएम 203 और डीएचएलएम 36-3 किस्म
- कोदो की उन्नत किस्में- जेके 41 और आरके 390-25 किस्म
- मिलेट्स की यह सभी किस्में किसानों को उनके खेतों में अच्छी उपज के साथ-साथ बाजार में अच्छा लाभ भी उपलब्ध करवाएंगी।

किसानों को देंगे सात हजार पौधे

रंग लाई मेहनत, अब एक ही पौधे से बैगन, टमाटर और मिर्च की फसल

भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसी फसल तैयार किया है जिसमें एक ही पौधे में से बैंगन,टमाटर और मिर्च की फसल तैयार कर सकते हैं। एक ही पौधे से बैंगन,टमाटर,और मिर्ची की खेती करने के लिए किसानों ने करीब पांच सालों तक इसपर शोध किया किया फिर जाकर इस पर जाकर सफलता मिली। वैज्ञानिकों ने अपने विशेष तकनीकि के माध्यम से एक ऐसा पौधा तैयार किया जिसमें एक ही पौधे से बैंगन,टमाटर और मिर्ची का उत्पादन हो सकेगा। इन पौधों को ब्रिमेटो और प्रोमैटो नाम दिया गया है।

कैसे तैयार किए जाते हैं ये पौधे

वैज्ञानिकों ने अपने अथक परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। इसमें उन्होंने बैंगन, टमाटर और मिर्ची के पौधे के तीन कलम बांधकर पौधे तैयार करने में ज्यादा पोषक तत्वों की जरुरत होती है। इसे तैयार करने में 50 से 60 दिनों का समय लग सकता है।

उत्पादन में 10 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी- इस पौधे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक सब्जी के पौधे की नर्सरी तैयार की जाती है उसके बाद उसमें कलम बांधकर दूसरे पौधे की नर्सरी को में लगाते हैं। इतना करने के बाद पौधे को मौसम के अनुकूल और उर्वरक, पानी और जरुरी पोषक तत्व दी जाती है। इस तकनीकी से जैविक और अजैविक तना के प्रबंधन कर उत्पादन में 10 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार पौधे का उत्पादन ज्यादा होता है।

किसानों को दिए जाएंगे पौधे

इस अनुसंधान के बाद इसकी खेती करने के लिए या ये कह लें इस पद्धति को लोगों को बताने के लिए पोमैटो व ब्रीमैटो के पौधे किसानों को दिए जा रहे है। आने वाले माह सात हजार और पौधे दिए जाएंगे। इसके लिए दो हजार से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्हें ग्राफ्टिंग चैंबर व डिब्बे में तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे खुद तैयार कर सकें।

रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से नकारात्मक परिणाम आए सामने

कृषि मंत्री ने किया आह्वान-मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अपनाएं प्राकृतिक खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान सोसायटी के 87वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि मृदा के बेहतर स्वास्थ्य के लिये प्राकृतिक खेती को अपनाया जाना जरूरी है। शुभारंभ अवसर पर डॉ. हिमांशु पाठक, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, डॉ. एसके चौधरी, डीडीजी एनआरएम आईसीएआर उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती सभी के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बेशक उत्पादन बंपर हुआ है, किंतु इसके नकारात्मक परिणाम भी हम सबके सामने हैं। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण न केवल मृदा की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, बल्कि उत्पादित अन्न, फल और सब्जियां मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए घातक होती है। मंत्री पटेल ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि इस प्रकार की नवीन तकनीक इजाद की जाये, जिसके उपयोग से प्राकृतिक खेती

को बढ़ावा मिले। इससे मनुष्य के साथ ही मृदा के स्वास्थ्य को भी संरक्षित किया जा सकेगा।

महानिदेशक, आईसीएआर डॉ. पाठक ने इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह एकमात्र सोसाइटी है, जो समर्पित प्रयासों के साथ 87 वर्षों से लगातार काम कर रही है। उन्होंने आशा की कि मृदा विज्ञान के प्रासंगिक क्षेत्र में नए उत्साह के साथ काम जारी रहेगा। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के दूसरे चरण, उर्वरक अनुसंधान पर उत्कृष्टता केंद्र, अधिक सटीक और शुरू करने पर जोर दिया। आईसीएआर-आईआईएसएस भोपाल के निदेशक डॉ. एसपी दत्ता ने जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए मिट्टी की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिट्टी एक मूल्यवान संसाधन है और मिट्टी की एक इंच परत बनने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं।

डॉ. डीआर बिस्वास को प्लेटिनम जुबली स्मरणोत्सव पुरस्कार

समारोह में डॉ. पाठक को मृदा विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन अनुसंधान योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए भारतीय मृदा विज्ञान सोसायटी की मानद सदस्यता, डॉ. चौधरी को एकीकृत मिट्टी और जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस वर्ष 2023 की मानद सदस्यता, डॉ. डीआर बिस्वास को प्लेटिनम जुबली स्मरणोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉ. पी.पी. महेंद्रन, डॉ. एमवीएस नायडू, डॉ. आरएम कर्माकर, डॉ. एसके गंगोपाध्याय को इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के फेलो के रूप में शामिल किया गया।

सरकार मसूर दाल की एमएसपी में भी 10 फीसदी तक की कर सकती है बढ़ोतरी

गेहूं अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगा

दिवाली से पहले केंद्र सरकार बढ़ाएगी रबी फसलों की एमएसपी और किसानों को मिलेगा फायदा!

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार किसानों को बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकती है। केंद्र सरकार रबी फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार गेहूं की एमएसपी में 150 से 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी कर सकती है। इससे खास कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान सबसे अधिक लाभांवित होंगे। इन्हीं राज्यों में सबसे अधिक गेहूं की खेती होती है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अगले साल के लिए गेहूं की एमएसपी में 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी कर सकती है। अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है, तो गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है। हालांकि, वर्तमान में गेहूं की एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा सरकार मसूर दाल की एमएसपी में भी 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है।

एमएसपी में हो सकती है 5 से 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

सरसों और सन फ्लावर की एमएसपी में 5 से 7 प्रतिशत का इजाफा किया जा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते में केंद्र सरकार रबी, दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी बढ़ाने के लिए मंजूरी दे सकती है। खास बात यह है कि एमएसपी में बढ़ोतरी करने का फैसला मार्केटिंग सीजन 2024- 25 के लिए लिया जाएगा।

23 फसलों को शामिल किया गया

कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। एमएसपी में 23 फसलों को शामिल किया गया है, 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और चार नकदी फसलें शामिले हैं। ऐसे रबी फसल की बोवनी अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच की जाती है। वहीं, फरवरी से मार्च और अप्रैल महीने के बीच इसकी कटाई होती है।

एमएसपी में शामिल फसलें

- अनाज- गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जो
- दलहन- चना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द,
- तिलहन- सरसों, सोयाबीन, सीसम, कुसुम, मूंगफली, सूरजमुखी, निगर्सिड
- नकदी- गन्ना, कपास, खोपरा और कच्चा जूट

वैज्ञानिकों की खोज से किसानों को नहीं उठाना पड़ेगा घाटा

विकसित की गेहूं की तीन नई किस्म अब बढ़ते तापमान में भी देंगी बंपर पैदावार

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारत गेहूं के उत्पादन में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसका कारण देश के कई कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थाएं हैं, जो नए और उन्नत बीजों को विकसित करती रहती हैं। आईसीएआर द्वारा गेहूं की तीन नई किस्में विकसित की गई हैं, जिन पर बढ़ते तापमान का ज्यादा असरा नहीं होगा और अच्छा उत्पादन देंगी। आईसीएआर द्वारा विकसित की गई गेहूं की यह नई किस्में तापमान आधारित हैं। गेहूं की यह नई किस्में डीबीडब्ल्यू 370 (करण वैदेही), डीबीडब्ल्यू 371 (करण वृंदा), डीबीडब्ल्यू 372 (करण वरुणा) हैं। गेहूं की यह किस्में आईसीएआर- भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित की गई हैं। यह सभी किस्में अपनी-अपनी जगह कई नए गुणों वाली हैं।

डीबीडब्ल्यू 371 (करण वृंदा)- गेहूं की यह किस्म वैज्ञानिकों ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा व उदयपुर सम्भाग को छोड़कर) पश्चिमी उत्तर प्रदेश (झांसी मंडल को छोड़कर), जम्मू कश्मीर के जम्मू और कठुआ जिले , हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला, पोंटा घाटी और उत्तराखंड क्षेत्रों के लिए विकसित की है। दरअसल गेहूं की यह फसल अगेती बुआई के लिए ज्यादा प्रभावी है और इन सभी क्षेत्रों में इस तरह की खेती प्रचलन में है। इसकी उत्पादकता एक हेक्टेयर में 87.1 क्विंटल है।

डीबीडब्ल्यू 370 (करण वैदेही)- इस किस्म की उत्पादकता 86.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. वहीं औसत उपज की बात करें तो यह किस्म 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 99 सेंटीमीटर तक होती है। सीजन में यह फसल लगभग 150 दिनों में तैयार हो जाती है।

डीबीडब्ल्यू 372 (करण वृंदा)

गेहूं की यह किस्म भी बम्पर पैदावार के लिए जानी जाएगी। इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार 85 क्विंटल तक है। वहीं इसकी औसत पैदावार की बात करें तो यह लगभग 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है। इसके पौधे की लंबाई भी अन्य से ज्यादा लगभग 95 सेंटीमीटर तक होती है।

रोग प्रतिरोधी हैं किस्में

आईसीएआर हरियाणा द्वारा विकसित की गई यह किस्में अन्य किस्मों से ज्यादा रोग प्रतिरोधी हैं। गेहूं में लगने वाले रोग पीला और भूरा रतुआ की सभी रोगजनक प्रकारों के लिए प्रतिरोधक का काम करती हैं यह किस्में। इसके साथ ही अगर आप इसके बीजों को खरीदना चाहते हैं तो आपको रबी की फसल के लिए यह बीज आईसीएआर-भारतीय गेहूँ और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा के सीड पोर्टल पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्र ने जारी की अधिसूचना

अच्छी पहल...राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना होगी

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत दिवस तेलंगाना में हल्दी किसानों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया- हमारे किसानों की भलाई और समृद्धि हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना करके, हमारा लक्ष्य हमारे हल्दी किसानों की क्षमता का उपयोग करना और उन्हें वह समर्थन देना है जिसके वे हकदार हैं। निजामाबाद के लिए लाभ विशेष रूप से अपरिमित हैं। हम अपने हल्दी किसानों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करते रहेंगे।

हल्दी प्राचीन काल से भारत में उगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भी है द्य विश्व में हल्दी का वैश्विक उत्पादन लगभग 11 लाख टन प्रति वर्ष है। विश्व उत्पादन परिदृश्य में भारत का दबदबा है और इसका योगदान 80 प्रतिशत है। चीन 8 फीसदी, म्यांमार 4 फीसदी, नाइजीरिया 3 फीसदी और बांग्लादेश 3 फीसदी का स्थान है।

मुरैना में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन, महिलाओं को दी गई समझाईश

मुरैना। कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरैना द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2023 से 02 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आर.के.एस. तोमर के नेतृत्व में किया जा रहा है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, मुरैना के सह-संचालक डॉ. संदीप तोमर इस कार्यक्रम में अतिथि के रुप में उपस्थित रहे। केन्द्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रीता मिश्रा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम की प्रभारी हैं। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र मुरैना ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसानों, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता का संदेश दिया गया। डॉ. आर.के.एस. तोमर ने ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर, घरेलू कचरा तथा कृषि कचरे के निष्पादन हेतु कम्पोस्टिंग एवं वर्मीकल्चर जैसे तरीके अपनाए जाने पर

बल दिया। डॉ. मिश्रा ने महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता और पोषण के महत्वपूर्ण सम्बन्ध के बारे में विस्तार से बताया तथा बीमारियों से बचने के लिए, भोजन को प्रदूषण से बचाने, विषाक्त भोजन से बचने और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्वच्छता अपनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होने बताया कि रसोई से प्राप्त होने वाले कचरे का विघटन कर देशी एवं पोषक तत्वों युक्त खाद तैयार की जा सकती है जिसका वर्षभर उत्पादन एवं उपयोग घर मे खाली पड़ी जगहों या छत पर लगाए गई पोषण वाटिका के लिए किया जा सकता है। कृषि महाविद्यालय ग्वालियर की बी.एस.सी. कृषि चर्तुथ वर्ष की रावे की छात्राओं द्वारा स्वच्छता संबधित संदेशों, पोस्टरों एवं नाटकों की प्रस्तुति के माध्यम से कृषि समुदाय को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने का प्रयास सराहनीय रहा।

केवी द्वारा निकरा परियोजना अंतर्गत कृषक संगोष्ठी का आयोजन

किसानों को सीखनी होगी कम पानी में फसल उगाने की तकनीकी: डॉ. एसपी सिंह

लहार (भिंड)। बदलते जलवायु परिवर्तन में खेती किसानी मैं तकनीकी को अपनाकर किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं। कम पानी की दशा में भी किसान तकनीकी को अपनाकर फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उक्त विचार कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लहार क्षेत्र के गिरवासा गांव में आयोजित कृषक संगोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. सिंह ने बताया कि भूगर्भ जल में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। इस कारण साल दर साल पानी नीचे खिसकता जा रहा है। वहीं वर्षा भी कम हो रही है। ऐसे में सिंचाई जल का समुचित प्रयोग करके पानी की 70 से 80 प्रतिशत तक बचत की जा सकती है। अधिकांश फसलों की जड़ें

दो से ढाई इंच के भीतर ही जाती हैं इसलिए फसलों को इस गहराई में ही पानी की आवश्यकता होती है। परंतु किसान खेत में 8 इंच तक पानी भर देता है जिससे पानी व्यर्थ जाता है और फसल के भी काम नहीं आता है। किसान सिंचाई की तकनीकी अपना कर पानी की इस बर्बादी को रोक सकते हैं। इसलिए किसानों को चाहिए कि खेतों का समतलीकरण करें, बौछारी एवं ड्रिप सिंचाई पद्धति का पालन करें। खेत में उतना ही पानी भरे जितना पौधों को आवश्यक है।

डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि कम पानी की दशा में मोटे अनाज की खेती बहुत लाभदायक होती है। मोटे अनाज भविष्य के अनाज हैं। इनकी खेती विषम जलवायु में, कम पानी की दशा में, ऊंची नीची जमीन पर कम लागत लगाकर आसानी से की जा सकती है। भिंड जिले की जलवायु व मिट्टी ज्वार बाजरा की खेती के लिए काफी अनुकूल भी है। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निकरा परियोजना के अंतर्गत किसानों को जलवायु के अनुकूल खेती व पशुपालन की पद्धतियों के बारे में अवगत करा रहा है। अवगत कराना हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र लहार द्वारा गिरवासा गांव को निकरा परियोजना के अंतर्गत चयनित कर गोद लिया गया है। जिसमें परियोजना से संबंधित सभी कार्य संचालित किए जाएंगे।

-उज्जैन की मंडी में आवक 10 हजार बोरी के पार पहुंची

सूखे सोयाबीन के भाव 4500 से 4700 रुपए क्विंटल मिले

दो साल से किसानों को नहीं मिल रहे पीले सोने के भाव

-नमी वाला सोयाबीन 2100 से 3500 रुपए क्विंटल बिक रहा

-मंडी नीलामी में लोकवन, पूर्णा गेहूं काफी तेज भाव में बिका

उज्जैन। जागत गांव हमार

दो दिन के अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी में पीले सोने की आवक तेजी से बढ़ने लगी है। एक दिन में मंडी नीलामी में 10 हजार बोरी से अधिक सोयाबीन की आवक दर्ज की गई। नीलामी में सोयाबीन 2500 से 4785 रुपए क्विंटल बिका। कारोबार करीब 5 करोड़ रुपए का बताया गया। मालवा के खेतों में सोयाबीन कट कर तैयार होने लगी है। अर्ली वैरायटी की सोयाबीन मंडियों में बिक्री के लिए आ रही है। इस बार किसानों को रबी की फसल में उत्पादन के साथ भाव में भी नुकसानी झेलना पड़ रही है। मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ने के साथ भाव धराशायी होते जा रहे हैं, जिससे किसान निराश हैं। बीते दो दिनों में नई सोयाबीन में 200 रुपए क्विंटल की मंदी

बताई गई। किसानों को नमी रहित सूखे सोयाबीन के भाव 4500 से 4700 रुपए क्विंटल मिल रहे हैं।

यहां सर्वाधिक बोवनी सोयाबीन की- नमी वाला सोयाबीन 2100 से 3500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। इस वर्ष भी सोयाबीन की तेजी को नकारा जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार आगामी दिनों में मंडियों में आवक बढ़ने पर 200 रुपए क्विंटल की मंदी और आ सकती है। जिले में रबी की फसल में सर्वाधिक क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की जाती है।

उज्जैन मंडी में गेहूं का रेट

किसानों को पीले सोने के भाव अच्छे मिलने की आस रहती है लेकिन बीते दो साल से सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे हैं। गेहूं बिका 3300, आवक 5000 बोरी मंगलवार को मंडी नीलामी में 5000 बोरी गेहूं की नीलामी की गई। ऊंचे में लोकवन गेहूं 3300 रुपए क्विंटल बिक गया।

गेहूं की बोवनी का रकबा बढ़ा

पूर्णा गेहूं के भाव ऊंचे में 3070 रुपए क्विंटल रहे। रबी की फसल कटने के बाद किसान गेहूं चने की बोवनी तैयारी करने लगेगा। ऐसे में अभी से गेहूं के बीज की मांग बनने लगी है। बीज वालों की पड़ताल के कारण गेहूं के भाव में तेजी आने लगी है। इस बार वर्षा भी पर्याप्त होने से गेहूं की बोवनी का रकबा भी बढ़ जाएगा। मंडी नीलामी में लोकवन, पूर्णा गेहूं काफी तेज भाव में बिक रहा है।

भोपाल सहित प्रदेश के 90 फीसदी मानसून की वापसी

रात में ठंड का अहसास बढ़ा अब गेहूं की बोवनी होगी

भोपाल। जागत गांव हमार

वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इस वजह से वर्षा का सिलसिला लगभग थम गया है। उधर, भोपाल से भी मानसून की विदाई हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक चंबल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर संभाग के जिलों से और रीवा, जबलपुर, शहडोल संभाग के अधिकांश हिस्सों से भी मानसून जा चुका है। अब यहां के किसान गेहूं की बोवनी में जुटने जा रहे हैं। वातावरण से नमी कम होने के कारण मौसम शुष्क होने लगा है। इस वजह से दिन में धूप में तल्खी महसूस होने लगी है लेकिन हवाओं का रुख उत्तरी होने से रात के समय ठंड का अहसास बढ़ गया है।

रीवा, शहडोल में थमी बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण झारखंड के आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के असर के कारण रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में हल्की वर्षा हो रही थी। यह मौसम प्रणाली अब बंगाल के आसपास पहुंच गई है। इस वजह से अब नमी आने का सिलसिला कम हो गया है। इसके चलते वर्षा का दौर भी लगभग थम गया है।

रात के तापमान में गिरावट

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि वातावरण से नमी कम होने के कारण मौसम शुष्क होने लगा है। आसमान साफ होने के कारण सुबह से ही धूप निकलने लगी है। दिन में तापमान बढ़ने से धूप में चुभन महसूस हो रही है। उधर, हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से शाम ढलते ही गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है। उत्तरी हवा के प्रभाव से रात के तापमान में गिरावट भी हो रही है।

-पिछले सीजन में जिन सहकारी समिति को केंद्र बनाया गया था

अंतिम तारीख पांच अक्टूबर अब तक हो पाए महज छह पंजीयन

जबलपुर। जागत गांव हमार

धान उपार्जन को लेकर शासन की ओर से शुरुआती दौर में जारी नीति के अनुसार पंजीयन की अंतिम तिथि पांच अक्टूबर रही। लेकिन अंतिम तारीख से ठीक पहले तक जिले में कुल पंजीयनों की संख्या केवल छह रही। कमोवेश ऐसी ही स्थिति पूरे प्रदेश में रही, जिसके चलते शासन स्तर से धान उपार्जन के लिए कराए जा रहे पंजीयनों की अंतिम तारीख को 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया। पटवारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने और इससे पहले ही सारा एप से खुद को अपने मोबाइलों से डिलीट किए जाने की वजह से कृषि भूमि पर लगाई गई फसलों की गिरदावरी नहीं हो पा रही थी। हड़ताल समाप्त होने के बावजूद पटवारियों को सारा एप री-इंस्टाल करने में अनेक प्रकार की परेशानियां हो रही थीं। जिनकी वजह से गिरदावरी का काम शुरु नहीं हो पा रहा था। इसी बीच

- गड़बड़ी रोकने एफपीओ-स्व सहायता समूहों को भी केंद्र नहीं बनाया
- धान विक्रय के पंजीयनों की अंतिम तारीख को 10 दिन आगे बढ़ाया
- कृषि भूमि पर लगाई गई फसलों की गिरदावरी नहीं हो पा रही थी

पंजीयन की अंतिम तारीख भी दस्तक देने लगी। चार अक्टूबर की रात तक जिले में महज छह पंजीयन हो पाए थे। ऐसे ही हालात पूरे प्रदेश में रहे, नतीजतन शासन की ओर से धान विक्रय के लिए पंजीयन कराने की तारीख 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई। खाद्य विभाग की ओर से धान पंजीयन के लिए जिले में 62 केंद्र बनाए गए हैं। शासन की ओर से पिछले सीजन में जिन सहकारी समिति को केंद्र बनाया गया था, उनमें से सात को सूची से बाहर कर दिया गया है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)